की उनमें भी बढ़ोत्तरी है और यदि हम किसी ब्रक ईवन प्वाइंट पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें कुछ विशेष प्रयास करने होंगे जो कि बहुत आवश्यक हैं ।

श्री दीपेन घोष : पोस्टल आर्डर पर कमीशन बढ़ाने से ? ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह : आपने तो पोस्टल आर्डर को ले लिया । ...

श्री दीपेन घोष : आपने पोस्टल आर्डर को क्या छोड़ दिया? ...(व्यवधान)

SHRI V. GOPALSAMY: It is a burden on the unemployed graduates.

SHRI DIPEN GHOSH: In this hypocrisy is unlimited.

SHRI ARJUN SINGH: The point is that we have to make that effort. It is in that direction of making that effort, that these tariffs have been revised. I would like to assure the House that at every stage we will make that effort to maximise efficiency and reliability, which together can only cater to the needs of the...

SHRI DIPEN GHOSH: You must tell us who will bear the cost?

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: It will lead to total inefficiency.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: I would like to know why at this point of time you have proposed this increase?

SHRI ARJUN SINGH: The point is that resources that are needed will have to be taken care of. if we want to proceed more quickly and go to what everyone desires, maximum utilisation and efficiency ... (*Interruptions*) ...

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Are you going to revise and withdraw?

SHRI ARJUN SINGH: I will do that also, but it has not been found possible ... (*Interruptions*) ...

SHRI DIPEN GHOSH: Are you going to withdraw the money order commission which you have raised, or not? (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please sit down.

SHRI ARJUN SINGH: If it had been possible to do all this without bringing this tariff to this House, I would have been the first to do it. The realities have to be faced and having done this we shall make every effort to see that the services are improved, maximum utilisation is made and efficiency is improved which ultimately alongwith this will come to a situation where we will be able to carry out out ... (*Interruptions*) ...

SOME HON. MEMBERS: Madam, we cannot associate ourselves with this. Therefore, as a protest, we walk out. [*At this stage some hon'ble Members left the Chamber*].

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, the House stands adjourned for lunch to meet again at 2-30 p.m.

The House then adjourned for lunch at fifty-six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock, **The Deputy Chairman** in the Chair.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS DURING THE WEEK COMMENCING THE 1ST DECEMBER, 1986

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) Madam Deputy Chairman, with your permission, I rise to announce the Government Business in this House during the week commencing 1st December, 1986, will consist of:

(1) Consideration and passing/return of the following Bills, as passed by Lok Sabha:

[Shri M. M. Jacob]

(a) The Indian Post Office (Amendment) Bill, 1986.

(b) The Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Bill, 1986, together with the Resolution seeking disapproval of the Coal Mines Nationalisation Laws (Amendment) Ordinance, 1986.

(c) The Delhi Apartment Ownership Bill, 1986.

(d) The Bureau of Indian Standards Bill, 1986.

(e) The Atomic Energy (Amendments Bill, 1986.

(f) The Customs and Excise Revenues Appellate Tribunal Bill, 1986.

(g) The Customs Tariff (Amendment) Bill, 1986.

(h) The Central Excise Tariff (Amendment) Bill, 1986.

(2) Consideration and passing of the Parsi Marriage and Divorce (Amendment) Bill, 1986.

RESOLUTION RE. CONTINUOUS MIGRATION OF POPULATION FROM VILLAGES TO THE METROPOLITAN CITIES AND REMEDIAL MEASURES THEREFOR—(contd.)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We now take up Private Members' Business. Further discussion on Resolution No. 1. Shri Ram Awadesh Singh.

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : उपसभापति महोदया, आज मैं सब से पहले माननीय सदस्य श्री कौशिक जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय पर सदन और सरकार का ध्यान खींचा है उस पर बहस कराई है लेकिन साथ ही साथ मैं सरकार की उदासीनता की ओर भी ध्यान खींचना चाहता हूं। सरकार इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी उदासीन है जिस का अन्दाज इसी से लगाया जा सकता है कि सरकारी बेंच पर केवल दो मन्त्री विराजमान हैं । महोदया इतना महत्वपूर्ण और गहन विषय है जिस पर बहुत गहराई से और बहुत संगीन हो कर विचार करने की जरुरत है । लेकिन लगता है कि सरकार इसको हल्के ढंग से ले रही है । (व्यवधान) यह जवाबदेही तो सरकार की है । हम लोग एक आदमी भी बोलें तो आप ध्यान से सुनें । यह बात आप नहीं कह सकते हैं कि हम एक हैं । हम अकेले भी हैं तो आप सब के बराबर हैं । महोदया, गांव का जो आज स्थिति है ऐसी हो गई है कि इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि गांवों से पलायन जारी है गांवों से पलायन एक वर्ग का जारी नहीं है, मजदूरों का जारी है, जो खेतिहर हैं उनका जारी है और बड़े किसानों का भी जारी है । इसके कई कारण हैं । एक कारण तो यह है कि जो आदमी मजदूर हैं उनको गांव में रोजगार नहीं रह गया है, उनकी गांव में इज्जत भी नहीं है । तो रोजी, रोटी और इज्जत की तलाश में शहर में भागते हैं । शहर में भी इज्जत नहीं मिलती है लेकिन उनको गांव के मुकाबले में शहर में रह कर थोड़ी सी उठ-बैठ, ठाठ-बाट, थोड़ी सी फुर्सत है लेकिन अभी तक शहर में भी उनका पेट अभी खाली है, यहां भी पेट खाली है । गांव में रोजगार के अवसर नहीं हैं । उसका मुख्य कारण यह है कि हमारी जो औद्योगिक नीति है वह इतनी खोखली है, हल्की हो गई है और इतनी बेजान हो गई है जिसका अन्दाज़ नहीं लगाया जा सकता है । 1956 में जो इंडस्ट्रीयल पालिसी बनी थी उस में इस बात का प्रावधान था कि लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जायेगी और गांवों में लघु उद्योगों को खोल कर खेती को सहारा दिया जाएगा । खेती अपने बूते पर बढ़ती हुई आबादी का